

The Gazette



of India

EXTRAORDINARY

PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

No. 116] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 1964/BHADRA 27, 1886

---

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

श्रम और रोजगार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1964

संख्या W B-20(3)/64.—भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या W B-20 (9)/61, तारीख 6 दिसम्बर, 1961 द्वारा औद्योगिक रोजगारों में काम करने वाले कामगारों के बोनस के प्रश्न का अध्ययन और उचित सिफारिशें करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था, जिसका गठन और जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :—

I—गठन

अध्यक्ष

श्री एम० आर० मेहर ।

स्वतंत्र सदस्य

1. श्री एम० गोविन्द रेड्डी, संसद् सदस्य ।
2. डा० बी० एन० गंगोली, निदेशक, अर्थशास्त्र का दिल्ली स्कूल ।

कामगारों के प्रतिनिधि सदस्य

1. श्री एस० आर० वासवदा ।
2. श्री एस० ए० डांगे ।

### नियोजकों के प्रतिनिधि सदस्य

1. श्री एन० डांडेकर ।

2. श्री डी० सांडिल्या ।

श्री डी० सांडिल्या के त्यागपत्र के फलस्वरूप श्री के० बी० माधुर को 4 जनवरी, 1963 से आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया ।

### II—विचारार्थ विषय

- (i) बोनस के स्वरूप की व्याख्या करना और औद्योगिक रोजगार के सम्बन्ध में लाभ के आधार पर बोनस की अदायगी के प्रश्न पर विचार करना तथा उक्त बोनस की संगणना के सिद्धांतों एवं अदायगी के तरीकों की सिफारिश करना ।

नोट :—“औद्योगिक रोजगार” पद में वे रोजगार सम्मिलित हैं जो निजी क्षेत्र में हैं और जो सरकारी क्षेत्र के उन संस्थानों में हैं जो कि विभाग द्वारा नहीं चलाये जाते और जो कि निजी क्षेत्र के संस्थानों से मुकाबला करते हैं ।

- (ii) उस सीमा का निर्धारण करना जहां तक कि बोनस की राशि वेतन के प्रचलित स्तर से प्रभावित हो ।

- (iii) (क) यह तय करना कि विभिन्न परिस्थितियों में पहले का खर्च क्या हो तथा उसकी गणना कैसे की जाये ।

(ख) उन परिस्थितियों को निश्चित करना जिनमें बोनस की अदायगी यूनिट क्रम में, उद्योग क्रम से और उद्योग-व-क्षेत्र क्रम से हो ।

- (iv) इस बात पर विचार करना कि कामगरों को जो बोनस निश्चित राशि से अधिक मिलना है वह राष्ट्रीय बचत सर्टीफिकेट के रूप में दिया जाये अथवा किसी और रूप में ।

- (v) यह विचार करना कि किन्हीं विशिष्ट संस्थानों में हानियों का विचार किए बिना कुछ नीची सीमायें और एक वर्ष में वितरण के लिए ऊंची सीमायें होनी चाहिए तथा यदि ऐसा हो तो निश्चित अवधि में हानियों और लाभ को आगे ले जाने की पद्धति पर विचार करना ।

- (vi) बोनस से संबद्ध झगड़ों को निपटाने के लिए उचित व्यवस्था और तरीकों का सुझाव देना ।

- (vii) बोनस से संबद्ध उन विषयों के सम्बन्ध में भी सुझाव देना जो कि नियोजकों (सरकारी क्षेत्र समेत) और कामगरों के प्रतिनिधियों द्वारा मान्य आधार पर आयोग के सामने रखे जायें ।

2. भारत सरकार द्वारा आयोग की रिपोर्ट 24 जनवरी, 1964 को प्राप्त हुई । पहले की तरह जनता के लिए इसकी प्रतियां प्रकाशन मैनेजर, दिल्ली की मार्फत बिक्री के लिए रख दी गई हैं ।

3. सरकार ने आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और उससे संलग्न नियोजकों के दो प्रतिनिधि सदस्यों में से एक के मतभेद-विवरण पर भली भाँति विचार किया है। सरकार ने आयोग की सिफारिशों को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार करने का फैसला किया है :—

- (i) बोनस के सम्बन्ध में “उपलब्ध अधिशेष” की संगणना के लिए वर्तमान सभी सीधे करों की कटौती अग्रता के रूप में होनी चाहिए।
- (ii) इसके अलावा उद्योगों को भावी विकास के लिए साधन जुटाने हेतु दी गई कर-रिआयतें कर्मचारियों को ज्यादा बोनस देने में इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। इसके विपरीत यदि कर सम्बन्धी वर्तमान कानून और विनियम इस सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से सुरक्षा नहीं करते तो कानून द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की कर-रिआयतों की राशियाँ वास्तव में उन्हीं प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हो जिनके लिए कर रिआयतें दी गई हैं। बोनस की अदायगी के लिए कुल लाभ निकालते समय सरकार द्वारा हिन्दुस्तान शिपयार्ड आदि कुछ संस्थाओं को दिए गए उपदानों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- (iii) जहाँ तक बोनस के लिए “उपलब्ध अधिशेष” की संगणना से पूर्व अग्रता के रूप में काटने लायक पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रश्न है, अधिमानात्मक शेयर पूंजी पर देय वास्तविक दर—प्रदत्त ईक्विटी पूंजी पर 8.5 प्रतिशत (करदेय) और रिजर्व निधि पर 6 प्रतिशत (करदेय)—बैंकों के अलावा किसी प्रतिष्ठान को नहीं दिए जाने चाहिए। बैंकों के लिए अनुरूपी दर अधिमानात्मक शेयर पूंजी पर देय वास्तविक दर होंगे—प्रदत्त ईक्विटी पूंजी पर 7.5 प्रतिशत (करदेय) और रिजर्व निधि पर 5 प्रतिशत (करदेय)।
- (iv) जहाँ तक पूर्वगामी निर्णयों द्वारा संशोधित बोनस आयोग की सिफारिशों के पूर्वपक्षी प्रभाव का सवाल है, वे उन मामलों को छोड़कर जिनमें समझौते अथवा निर्णय हो चुके हैं, कैलेन्डर-वर्ष 1962 में किसी भी दिन समाप्त होने वाले लेखा-वर्ष से सम्बन्धित बोनस के ऐसे सभी मामलों पर लागू होंगे जिनमें विवाद चल रहा है।

4. सरकार यह वांछनीय समझती है कि एक निश्चित स्तर से ऊपर बोनस बचत-सर्टीफिकेट अथवा अन्य उपयुक्त निवेश के रूप में दिया जाए। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सम्बन्धित पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ, एक बैठक बुलाई जाए ताकि यह समझौता हो जाए कि अमुक स्तर से अधिक बोनस की नकद अदायगी वांछनीय होगी और इस स्तर से फालतू बोनस किस प्रकार की बचतों में लगाया जा सकता है।

5. उपर्युक्त निर्णयों के प्रकाश में सरकार ऐसा विधान बनाने का विचार करती है जिसमें ऐसे सिद्धांत हों जिनसे न्यायाधिकरणों या अन्य न्यायिक निकायों को, जब कभी उनके सामने बोनस के बारे में विवाद आएँ, मार्गदर्शन मिल सके। सरकार आशा करती है

कि प्रस्तावित विधान के बनने तक सम्बन्धित पक्ष बोनस का मामला तय करने में स्वेच्छा से उपर्युक्त निर्णय लागू करेंगे ।

6. भारत सरकार आयोग द्वारा किए गए काम के सम्बन्ध में प्रशंसा-भाव व्यक्त करती है ।

पी० एम० मेनन, सचिव ।

11-9-64

संख्या डब्ल्यू बी-20(3)/64 नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1964

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रति निम्नलिखित को भेजा जाये :—

- (i) सभी राज्य सरकारें और केन्द्र प्रशासित प्रदेश ।
- (ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और आयोजना आयोग ।
- (iii) मालिक और मजदूरों के अखिल भारतीय संगठन ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के असाधारण राजपत्र में ग्राम सूचना के त्तिये प्रकाशित किया जाये ।

पी० एम० मेनन, सचिव